[2025] 4 एस.सी.आर. 608 : 2025 आईएनएससी 471

कर्नाटक राज्य

बनाम

श्री चन्नाकेशव.एच.डी. और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या - 1849/2025)

08 अप्रैल 2025

[सुधांशु धूलिया* और के. विनोद चंद्रन, जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

क्या हाई कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 की धारा 13(1)(b) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13(2) के तहत, अनुपातहीन संपत्ति के मामले में उत्तरदाता सं.1-सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफ.आई.आर. रद्द करके गलती की, इस आधार पर कि पुलिस अधीक्षक (**एस.पी**) ने एफ.आई.आर. दर्ज करने का आदेश देने से पहले प्रारंभिक जांच नहीं की?

हेडनोट्स †

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 – धारा 13(1)(b), 13(2), 17 – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले - क्या प्रारंभिक जांच अनिवार्य है:

निर्णय: नहीं - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 या 17 के तहत प्रारंभिक जांच का कोई प्रावधान नहीं है - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 का दूसरा परंतुक प्रारंभिक जांच के बारे में बात नहीं करता है - हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच वांछनीय है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है - ऐसे मामले में जहां एक वरिष्ठ अधिकारी, एक विस्तृत स्रोत रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें संज्ञेय अपराध होने का खुलासा होता है, एफ.आई.आर दर्ज करने का आदेश देता है, तो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता में छूट दी जा सकती है - वर्तमान मामले में, प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं थी क्योंकि पुलिस अधीक्षक के पास पहले से ही स्रोत रिपोर्ट के रूप में विस्तृत जानकारी थी, जिसमें कार्यवाही शुरू करने के कारणों और विवरणों की जानकारी दी गई थी - इस प्रकार, पुलिस अधीक्षक ने स्रोत रिपोर्ट के रूप में उनके सामने रखे गए सबूतों के आधार पर उत्तरदाता सं. 1 के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज करने का आदेश पारित किया था - उच्च न्यायालय को एफ.आई.आर रद्द नहीं करनी चाहिए थी - विवादित आदेश रद्द किया जाता है। [पैरा 8, 15, 16]

कर्नाटक राज्य बनाम श्री चन्नाकेशव. एच. डी. और अन्य

उद्धृत केस लॉ

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य **[2013] 14 एस.सी.आर. 713: (2014) 2 एस.सी.सी 1;** पी. सिराजुद्दीन बनाम मद्रास राज्य **[1970] 3 एस.सी.आर 931: (1970) 1 एस.सी.सी 595;** कर्नाटक राज्य बनाम टी.एन. सुधाकर रेड्डी, **2025 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 382;** सी.बी.आई बनाम थोम्मांडरू हन्ना विजयलक्ष्मी **[2021] 13 एस.सी.आर 364: (2021) 18 एस.सी.सी 135 - संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

कीवर्ड की सूची

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 का परंतुक; भ्रष्टाचार के मामले; रद्द करना; धारा 482 सी.आर.पी.सी; अनुपातहीन संपत्ति; लोक सेवक; प्रारंभिक जांच; स्रोत रिपोर्ट; पुलिस अधीक्षक (एस.पी); ललिता कुमारी फैसला।

मामला उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1849/2025 कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के रिट याचिका संख्या 28052/2023 में दिनांक 25.04.2024 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध।

पार्टियों में उपस्थिति

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: देवदत्त कामत, सीनियर एडवोकेट, निशांत पाटिल, आयुष पी शाह, अरिजीत डे, मेहुल कुमार गर्ग।

उत्तरदाता के अधिवक्ता: रंजीत कुमार, सीनियर एडवोकेट, कुमार परिमल, स्मरहर सिंह।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

सुधांशु धूलिया, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. कर्नाटक राज्य ने फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा 25.04.2024 को पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसमें माननीय सिंगल जज ने उत्तरदाता सं.1 (श्री चन्नाकेशव

एच.डी.) के खिलाफ राज्य द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया था। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'पी.सी एक्ट') की धारा 13(1)(b) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13(2) के तहत अपराधों से संबंधित था, जो कि अनुपातहीन संपत्ति (या डी.ए केस जैसा कि इसे कहा जाता है) का मामला है।

3. साल 1998 में, उत्तरदाता नंबर 1 को कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर नियुक्त किया गया था। बाद में, उन्हें बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन (संक्षेप में 'बी.ई.एस.सी.ओ.एम') में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर प्रमोट किया गया।

4. अभियोजन पक्ष के अनुसार, उत्तरदाता सं.**1** ने सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम करते हुए गैर-कानूनी तरीके से खुद को अमीर बनाया था और इसके परिणामस्वरूप, 04.12.2023 को थाना कर्नाटक लोकायुक्त, बैंगलोर टाउन (बैंगलोर) में पी.सी एक्ट की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत एक एफ.आई.आर (नंबर 54/2023) दर्ज की गई। इसके बाद, जांच शुरू हुई।

5. रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने ऊपर बताई गई एफ.आई.आर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। एफ.आई.आर को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि पी.सी एक्ट की धारा 17 के दूसरे प्रोविज़ो का उल्लंघन हुआ है, जिसमें यह ज़रूरी है कि धारा 13 के सब-सेक्शन 1 के क्लॉज़ (b) में बताए गए अपराध के संबंध में, पुलिस अधीक्षक (संक्षेप में 'एस.पी') के रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना जांच नहीं की जा सकती। पी.सी एक्ट की धारा 17 इस प्रकार है:

> "**17.** जांच करने के लिए अधिकृत व्यक्ति–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) 38 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी पुलिस अधिकारी जो निम्नलिखित रैंक से नीचे का न हो,—
>
> **(ए)** दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के मामले में, एक पुलिस इंस्पेक्टर का;
>
> **(बी)** बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन इलाकों में और किसी भी अन्य मेट्रोपॉलिटन इलाके में एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस जिसे कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 (1974 का 2)39 की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किया गया हो,
>
> **(सी)** अन्य जगहों पर, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उसके बराबर रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा,
>
> इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की जांच मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट

या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं की जाएगी, जैसा भी मामला हो, और न ही बिना वारंट के कोई गिरफ्तारी की जाएगी:

बशर्ते कि यदि पुलिस इंस्पेक्टर के पद से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत किया जाता है, तो वह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी ऐसे किसी अपराध की जांच कर सकता है, जैसा भी मामला हो, या बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है:

बशर्ते कि सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (1) के क्लॉज़ (b) में बताए गए अपराध की जांच, पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं की जाएगी।" (जोर दिया गया)

6. कर्नाटक हाई कोर्ट के विद्वान सिंगल जज की राय थी कि हालांकि एफ.आई.आर दर्ज होने से पहले, पुलिस अधीक्षक ('एस.पी') से आदेश आए थे, लेकिन एस.पी ने अपने आदेश देने से पहले कोई शुरुआती जांच नहीं की थी और इसलिए, एस.पी ने कोई दिमाग नहीं लगाया था। हाई कोर्ट के विद्वान जज की राय में, इससे पूरी कार्यवाही प्रभावित होगी और इस तरह, हाई कोर्ट ने 25.04.2024 के आदेश से एफ.आई.आर को रद्द कर दिया।

7. कर्नाटक राज्य ने इस हाई कोर्ट के आदेश को इस कोर्ट में चुनौती दी है, जिसका मुख्य आधार यह है कि उक्त प्रावधान के तहत कल्पना की गई शुरुआती जांच ज़रूरी तो है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा, कर्नाटक राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि, इस मामले में, एस.पी ने पी.सी एक्ट की धारा 17 के तहत 04.12.2023 को एक आदेश पारित किया था और यह आदेश संबंधित सामग्रियों पर विचार करने के बाद पारित किया गया था, क्योंकि यह 05.10.2023 की एक सोर्स रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था।

8. पी.सी एक्ट की धारा 13 या धारा 17 के तहत शुरुआती जांच का कोई प्रावधान नहीं है। पी.सी एक्ट की धारा 17 का दूसरा प्रोविज़ो शुरुआती जांच के बारे में बात नहीं करता है। यह सिर्फ़ **ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य (2014) 2 SCC 1** के मामले में ही इस कोर्ट ने कहा था कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले, शुरुआती जांच करना ज़रूरी है। **ललिता कुमारी (सुप्रा)** से बहुत पहले, इस कोर्ट ने **पी. सिराजुद्दीन बनाम स्टेट ऑफ़ मद्रास (1970) 1 SCC 595** में कहा था कि "किसी सरकारी कर्मचारी पर, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो,

सार्वजनिक रूप से बेईमानी के ऐसे कामों का आरोप लगाने से पहले, जो इस मामले में लगाए गए गंभीर दुर्व्यवहार या कदाचार के बराबर हों और उसके खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए, एक ज़िम्मेदार अधिकारी द्वारा आरोपों की कुछ उचित शुरुआती जांच होनी चाहिए।" इस फैसले पर भरोसा करते हुए, **ललिता कुमारी (सुप्रा)** ने भ्रष्टाचार के मामलों को उन मामलों की कैटेगरी में रखा था जिनमें एफ.आई.आर दर्ज करने से पहले शुरुआती जांच की जा सकती है। **ललिता कुमारी (सुप्रा)** का संबंधित हिस्सा इस प्रकार है:

> "**117.** भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों के मामले में, इस कोर्ट ने पी. सिराजुद्दीन [पी. सिराजुद्दीन बनाम स्टेट ऑफ़ मद्रास, (1970) 1 SCC 595 : 1970 SCC (Cri) 240] मामले में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले शुरुआती जांच की ज़रूरत बताई थी।
>
> .....
>
> **निष्कर्ष/निर्देश**
>
> **120.** उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम यह मानते हैं:
>
> .....
>
> **120.6.** किस तरह की और किन मामलों में शुरुआती जांच की जाएगी, यह हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जिन मामलों में शुरुआती जांच की जा सकती है, उनकी कैटेगरी इस प्रकार है:
>
> **(ए)** वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद
>
> **(बी)** वाणिज्यिक अपराध
>
> **(सी)** चिकित्सा लापरवाही के मामले
>
> **(डी)** <u>भ्रष्टाचार के मामले</u>
>
> **(ई)** ऐसे मामले जहां आपराधिक मुकदमा शुरू करने में असामान्य देरी/लापरवाही होती है, उदाहरण के लिए, मामले की रिपोर्ट करने में 3 महीने से ज़्यादा की देरी, जिसके कारणों का संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिया गया हो।"
>
> (जोर दिया गया)

हालांकि, कर्नाटक राज्य के विद्वान वकील यह तर्क देंगे कि जब एस.पी के सामने एक डिटेल्ड सोर्स रिपोर्ट होती है, जिसमें कार्यवाही शुरू करने के कारणों के बारे में बताया गया हो और

जब डिटेल्स दी गई हों, तो औपचारिक शुरुआती जांच ज़रूरी नहीं हो सकती क्योंकि सभी ज़रूरी मटेरियल पहले से ही एस.पी के सामने मौजूद है।

9. सोर्स रिपोर्ट उत्तरदाता सं. 2 - डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डी.एस.पी) ने तैयार की थी और उसे एस.पी को सबमिट किया गया था। 05.10.2023 की सोर्स रिपोर्ट इस प्रकार है:

सेवा में
पुलिस अधीक्षक-01
कर्नाटक लोकायुक्त
बैंगलोर सिटी डिवीजन
बैंगलोर
महाशय,
विषय: श्री चन्नाकेशवा एच.डी., एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो वर्तमान में '**बी.ई.एस.सी.ओ.एम**', जयनगर डिवीजन, बनशंकरी I स्टेज, बैंगलोर में कार्यरत हैं, के ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में सोर्स रिपोर्ट जमा करना - संदर्भ:
ऊपर बताए गए विषय के संबंध में, मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह पता चला है कि श्री चन्नाकेशव एच.डी., एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो अभी 'बी.ई.एस.सी.ओ.एम', जयनगर डिवीजन, बनशंकरी I स्टेज, बैंगलोर में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आय से ज़्यादा की प्रॉपर्टी हासिल की है।
श्री चन्नाकेशव 11-11-1998 को कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुनिराबाद में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर शामिल हुए और फिर '**बी.ई.एस.सी.ओ.एम**', कोरमंगला डिवीजन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर प्रमोट हुए और उसके बाद हेब्बल डिवीजन में काम किया और अभी वह जयनगर डिवीजन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (V) के तौर पर काम कर रहे हैं।
<u>भ्रष्टाचार का स्रोत</u>
ऐसी जानकारी मिली है कि अपने सरकारी कार्यकाल के दौरान उन्होंने तीसरे पक्षों (बेनामी) और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बहुत ज़्यादा अवैध संपत्ति जमा की है।

फिर अधिकारी की संपत्ति का ब्यौरा देने के बाद, सोर्स रिपोर्ट इस तरह खत्म होती है:

> जैसा कि ऊपर बताया गया है, पहली नज़र में यह पाया गया है कि श्री चन्नाकेशवा एच.डी. ने चेक पीरियड यानी सरकारी नौकरी में शामिल होने की तारीख 11-11-1998 से 30-09-2023 तक अपनी जानी-मानी इनकम के सोर्स से ज़्यादा प्रॉपर्टी हासिल की है, जो कि Rs. 6,64,67,000/- है, जो 92.54% बनता है। यह भी पता चला है कि ऊपर बताए गए एस.जी.ओ. के पास बैंगलोर शहर और दूसरी जगहों पर अपने नाम पर या तीसरे पक्षों (बेनामी) के नाम पर कुछ और गैर-कानूनी/आय से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती हैं। अगर बैंगलोर में उनके अपने घर और श्रीरामपुरा मेन रोड, अमृतहल्ली, जक्कूर में दूसरे घरों, नागवारा में ससुर के घर, एस.जी.ओ. की काम करने की जगह और उनकी बहन के घर पर तलाशी ली जाए, तो उनकी जानी-मानी इनकम के सोर्स से ज़्यादा चल और अचल संपत्ति, सोना, चांदी के सामान, कैश और बैंक डिपॉजिट मिलने की संभावना है। इसलिए, ऊपर बताए गए सरकारी कर्मचारी के खिलाफ पी.सी एक्ट 1988 की धारा 13(2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13(l)(b) के तहत मामला दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

10. इस सोर्स रिपोर्ट के अनुसार, पहली नज़र में यह पाया गया कि उत्तरदाता सं. 1 ने जांच की अवधि यानी 11.11.1998 से 30.09.2023 के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से ज़्यादा संपत्ति जमा की थी, जो कि 6,64,67,000 रुपये थी। इस सोर्स रिपोर्ट के आधार पर, जो कि एक तरह की शुरुआती जांच है, एस.पी ने उत्तरदाता सं. 1 के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज करने का आदेश दिया।

11. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट श्री देवदत्त कामत, इस बात पर ज़ोर देने के लिए कि पी.सी एक्ट के तहत एफ.आई.आर दर्ज करने से पहले जांच ज़रूरी नहीं है, **स्टेट ऑफ़ कर्नाटक बनाम टी.एन सुधाकर रेड्डी** 2025 **एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी** 382 में इस कोर्ट के फैसले पर भरोसा करेंगे। **ललिता कुमारी (सुप्रा)** में बताए गए कानून पर विचार करने के बाद, इस कोर्ट ने **टी.एन सुधाकर रेड्डी (सुप्रा)** में इस प्रकार कहा:

> **"19. ...** शुरुआती जांच की ज़रूरत हर मामले के खास तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार के मामले ऐसी कैटेगरी में आते हैं जहां शुरुआती जांच 'की जा सकती है'।

20. जैसा कि ललिता कुमारी (सुप्रा) में बताया गया है, 'किया जा सकता है' शब्द का इस्तेमाल इस बात पर ज़ोर देता है कि ऐसी जांच करना विवेकाधीन है और कोई अनिवार्य ज़िम्मेदारी नहीं है।

21. ललिता कुमारी (सुप्रा) के तर्क के आधार पर, इस कोर्ट ने मनागिपेट (सुप्रा) में यह माना कि हालांकि ललिता कुमारी (सुप्रा) के फैसले में यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार के कथित मामलों में शुरुआती जांच ज़रूरी है, लेकिन इससे आरोपी को शुरुआती जांच की मांग करने का अधिकार नहीं मिल जाता। शुरुआती जांच की जानी है या नहीं, यह हर मामले के खास तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, और इसे अनिवार्य शर्त नहीं कहा जा सकता, जिसके बिना भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में आरोपी के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज नहीं की जा सकती।" (जोर दिया गया)

आगे, उक्त मामले में इस न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि:

"**51.** ऊपर की चर्चा को देखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि:

ए).....

बी) पी.सी एक्ट के तहत हर मामले में शुरुआती जांच ज़रूरी नहीं है। अगर किसी सीनियर ऑफिसर के पास सोर्स इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है जो डिटेल्ड और अच्छी तरह से तर्कसंगत है और ऐसी है कि कोई भी समझदार व्यक्ति यह मानेगा कि यह पहली नज़र में किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, तो शुरुआती जांच से बचा जा सकता है। (जोर दिया गया)

12. संक्षेप में, इस कोर्ट ने माना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में शुरुआती जांच, हालांकि ज़रूरी है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। ऐसे मामले में जहां एक सीनियर ऑफिसर, एक विस्तृत सोर्स रिपोर्ट के आधार पर जिसमें संज्ञेय अपराध होने का खुलासा होता है, एफ.आई.आर दर्ज करने का आदेश देता है, तो शुरुआती जांच की ज़रूरत को कम किया जा सकता है।

13. फिर भी, उत्तरदाता सं.**1** के विद्वान सीनियर एडवोकेट श्री रंजीत कुमार यह तर्क देंगे कि एफ.आई.आर दर्ज होने से पहले उत्तरदाता सं.1 को अपनी बात समझाने का मौका कभी नहीं दिया गया। वह आगे यह भी तर्क देंगे कि एफ.आई.आर का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारी को परेशान करने के लिए एक हथियार के तौर पर किया गया है और यह ऐसा मामला है जहाँ अधिकारी (उत्तरदाता सं.**1**) को कोई पहले से नोटिस या सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, जो कि अगर शुरुआती जाँच हुई होती तो दिया जा सकता था।

14. सीनियर वकील श्री देवदत्त कामत ने इस कोर्ट के हाल के तीन जजों की बेंच के फैसले, **सी.बी.आई बनाम थोमांड्रू हन्ना विजयलक्ष्मी (2021) 18 एस.सी.सी 135** पर भरोसा किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि आरोपी सरकारी कर्मचारी को एफ.आई.आर दर्ज होने से पहले कथित बेहिसाब संपत्ति के बारे में सफाई देने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी भी राय है कि यह सही कानूनी स्थिति है क्योंकि इस स्टेज पर किसी सरकारी कर्मचारी को सुने जाने का कोई स्वाभाविक अधिकार नहीं है।

15. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, यह साफ़ है कि इस मामले में शुरुआती जांच ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि एस.पी के पास ऊपर बताए गए सोर्स रिपोर्ट के रूप में पहले से ही पूरी जानकारी थी। हमने एस.पी द्वारा जारी किया गया वह आदेश भी देखा है, जिसमें उत्तरदाता सं.**1** के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, जिससे पता चलता है कि एस.पी ने वह आदेश सोर्स रिपोर्ट के रूप में उनके सामने रखे गए सबूतों के आधार पर दिया था।

16. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हमारी यह राय है कि हाई कोर्ट को इस मामले में एफ.आई.आर को रद्द नहीं करना चाहिए था। इसलिए, हम इस अपील को मंज़ूरी देते हैं और 25.04.2024 का विवादित आदेश रद्द किया जाता है।

17. यदि कोई अंतरिम आदेश है, तो उसे रद्द किया जाता है।

18. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो उनका निपटारा कर दिया गया है।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।